**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2670**

**14 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए**

**'ऑपरेशन खनिज खोज'**

**2670. श्री विद्युत वरण महतोः**

**डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़ः**

**श्री गजानन कीर्तिकरः**

**डॉ॰ जे॰ जयवर्धनः**

**श्री सुधीर गुप्ताः**

**श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः**

**कुँवर हरिवंश सिंहः**

**श्री एस॰ आर॰ विजय कुमारः**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत के भौगोलिक सर्वेक्षण (जीएसआई) का 'ऑपरेशन खनिज खोज' प्रारंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रचालन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या क्षेत्रीय अन्वेषण हेतु 100 खनिज खण्ड की जीएसआई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण के लिए ई-नीलामी को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी 6600 से अधिक अन्वेषण रिपोर्टों को सार्वजनिक करने के लिए डिजिटलीकृत करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) खनिज अन्वेषण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**<u>खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)</u>**

(क) : जी हां । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) अपने क्षेत्र कार्य सत्र 2016-17 में 'परियोजना अनावृत' (ऑपरेशन खनिज खोज) के अंतर्गत दो बहुविधा मार्गदर्शक (पायलट) सहयोग परियोजनाओं पर कार्य करेगा । इस परियोजना के अंतर्गत जीएसआई अरावली-बुन्देलखंड क्रेटन के उत्तरी भाग और धारवाड क्रेटन के पश्चिम से पूर्वी भाग में कार्य करेगा । मार्गदर्शन (पायलट) अध्ययन तीन वर्षों में पूर्ण करने की योजना है । इन परियोजनाओं का ध्येय और उद्देश्य मोटे अवसाद आवरण के नीचे छिपे हुए और गहराई में स्थित खनिज निक्षेपणों की खोज करना है ।

(ख) : जीएसआई ने क्षेत्रीय गवेषण हेतु 108 खनिज ब्लॉकों की पहचान की है । ये ब्लॉक 23 राज्यों यथा राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, और सिक्किम में स्थित हैं ।

खान मंत्रालय, देश के खनिज संसाधनों (गैर-ईंधन और गैर-कोयला) के विस्तृत गवेषण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एनएमईपी) को अंतिम रूप देने के लिए कार्य कर रहा है । इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ एक पारदर्शी पद्धति के द्वारा खनिज गवेषण में निजी उद्यमियों की भागीदारी का प्रस्ताव किया गया है । एनएमईपी को अंतिम रूप देने के पश्चात इन ब्लॉकों की नीलामी की जा सकती है ।

(ग) : जीएसआई अपनी गवेषण रिपोर्टों को डिजीटाइज कर रहा है जिसको जून, 2016 तक पूरा करने की योजना बनाई जा रही है । तत्पश्चात इन रिपोर्टों को जीएसआई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

(घ) : सरकार द्वारा प्रस्तावित एनएमईपी में खनिज गवेषण क्षेत्र में निजी निवेश में तेज़ी लाने के अनेक प्रयासों की परिकल्पना की गई है । इन में से कुछ प्रयासों में सार्वजनिक प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता आधाररेखा भूवैज्ञानिक आंकड़ा स्थापन, गवेषण एजेंसियों को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है ।

*****